



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मई 31, 2001/ज्येष्ठ 10, 1923

No. 137]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2001/JYAISTHA 10, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2001

सं. टीएएमपी/12/99-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार इस प्राधिकरण के 29 अक्टूबर, 1999 के आदेश को लागू करने के लिए दिए गए स्थगन को जारी रखने के कंडला पत्तन न्यास के प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/12/99-केपीटी

कंडला पत्तन न्यास (केपीटी)

आवेदक

आदेश

(मई, 2001 के 16वें दिन पारित किया गया)

इस प्राधिकरण ने 29 अक्टूबर 1999 को कंडला पत्तन न्यास (केपीटी) के गांधीधाम टाउनशिप भूमि के दर ढांचे के संशोधन से संबंधित एक आदेश पारित किया था। यह आदेश 25 नवम्बर, 1999 को राजपत्र सं. 98 के रूप में अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त आदेश के प्रत्युत्तर में, इस प्राधिकरण को विभिन्न संगठनों से इसकी समीक्षा के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से, कंडला पत्तन कर्मचारी संघ (केपीकेएस) ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष योजना के अधीन कर्मचारियों को आबंटित किए गए प्लॉटों के आदेश के कार्यक्षेत्र से छूट का अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन भेजा था। केपीकेएस के अनुरोध पर विचार करते हुए, इस आदेश की समीक्षा करने और अभ्यावेदन को 'समीक्षा मामला' के रूप में पंजीकरण करने का निर्णय इस प्राधिकरण द्वारा लिया गया था। केपीटी को अंतिम निर्णय लिए जाने तक भारत सरकार की विशेष योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को आबंटित प्लॉटों से संबंधित संशोधित दरों के कार्यान्वयन को स्थगित रखने का सुझाव दिया गया था।

3.1 इस बीच, इस आदेश के विरुद्ध अन्य प्रयोक्ताओं से और अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। समीक्षा मामले की संयुक्त सुनवाई 8 मार्च, 2000 को केपीटी में की गई थी।

3.2. संयुक्त सुनवाई की कार्यवाही के दौरान, केपीकेएस के अभ्यावेदन के मामले में प्राधिकरण के आदेश को रोकने की बात आई थी और अन्यो के मामले में नहीं। केपीटी ने भी यह महसूस किया था कि समीक्षा मामले के निपटान तक पूरे आदेश को रोकना उपयुक्त होगा। तदनुसार, समीक्षा मामले के निपटान तक इस आदेश के कार्यान्वयन को रोका गया था। यह कार्यवाई इस संबंध में केपीटी से प्राप्त औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा किया गया था।

3.3. संयुक्त सुनवाई के समय केपीटी ने आवस्त किया था कि गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर ढांचा के संशोधन से संबंधित मामले पर उसके न्यासी बोर्ड की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसके पश्चात् केपीटी लिखित निवेदन करेगा। इस प्राधिकरण ने इस स्थिति को ध्यान में रखकर समीक्षा मामले के निपटान तक स्थिति को जस का तस बनाए रखने का निर्णय लिया था।

4.1. अपने न्यासी बोर्ड की बैठक में इस मामले पर चर्चा करने के पश्चात् अपना लिखित निवेदन करने के लिए केपीटी को कई अनुस्मारक जारी किए गए थे। पत्तन लगातार आवस्त कर रहा था कि इस मामले पर इसके न्यासी बोर्ड द्वारा शीघ्र ही चर्चा की जाएगी। बोर्ड का पुनर्गठन, कच्छ क्षेत्र में भूकम्प आदि देरी के कारण दर्शाए गए थे।

4.2. केपीटी ने 2 अप्रैल, 2001 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि गांधीधाम टाउनशिप भूमि के दर ढांचे में संशोधन के प्रस्ताव को 2 मार्च, 2001 को आयोजित बोर्ड की बैठक की कार्यसूची में शामिल किया गया था और बोर्ड ने 26 जनवरी, 2001 को अभूतपूर्व भूकम्प के कारण अर्थव्यवस्था और आदिपुर-गांधीधाम-कंडला परिसर में सिविल ढांचों को हुए भारी नुकसान के मद्देनजर इस प्राधिकरण से पहले दिए गए स्थगन को जारी रखने का प्रस्ताव किया।

5. केपीटी से प्रत्युत्तर में पहले ही अत्यंत देर हो चुकी है। इस बीच, जबरदस्त भूकम्प ने कच्छ क्षेत्र को नष्ट कर दिया था। इस क्षेत्र में भूकम्प के परिणामस्वरूप उत्पन्न असाधारण स्थिति को उद्भूत करते हुए केपीटी बोर्ड द्वारा किया गया अनुरोध उचित है और तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

6. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त तर्कों और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण केपीटी के गांधीधाम टाउनशिप भूमि के दर ढांचे के संशोधन से संबंधित 29 अक्टूबर, 1999 के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए दिए गए स्थगन को इस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से अगले छह माह की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय करता है। यह प्राधिकरण केपीटी को अपना लिखित निवेदन देने के लिए बढ़ाई गई समयवाधि का अनुसरण करने का भी निदेश देता है, ऐसा न करने पर यह प्राधिकरण इस मामले में अपनी ओर से कार्यवाई करने के लिए बाध्य होगा।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/01-असाधारण]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2001

No. TAMP/12/99-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the Kandla Port Trust to continue with the stay granted for implementation of this Authority's Order dated 29 October 1999, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/12/99-KPT

The Kandla Port Trust (KPT)

..... Applicant

ORDER

(Passed on this 16th day of May 2001)

This Authority had passed an Order on 29 October, 1999 relating to revision of the rate structure of Gandhidham Township land of the Kandla Port Trust (KPT). The Order was notified on 25 November, 1999 as Gazette No. 98.

2. In response to the said Order, this Authority received a number of representations from various organisations for a review. In particular, the Kandla Port Karamchari Sangh (KPKS) has sent a representation requesting to exempt

from the purview of the order the plots allotted to the employees under a special scheme sanctioned by the Government of India. Considering the request of the KPKS, it was decided by this Authority to review the Order and to register the representation as a 'review case'. The KPT was advised to keep in abeyance implementation of the revised rates pertaining to the plots allotted to employees under the special scheme of the Government of India till a final decision was taken.

3.1. In the meanwhile, more representations were received against the Order from other users. A joint hearing was held in the review case on 8 March, 2000 at the KPT.

3.2. During the course of the joint hearing, a point came up about staying the Authority's Order in respect of the KPKS representation and not in respect of others. The KPT also felt, that it would be appropriate to stay the entire order until the disposal of the review case. Accordingly, implementation of the Order was stayed until disposal of the review case. This was followed up by a formal communication in this regard to the KPT.

3.3. At the joint hearing, the KPT assured that the matter relating to the revision of the rate structure of the Gandhidham township land would be discussed again in the next meeting of its Board of Trustees whereafter the KPT would make a further written submission. This Authority took note of this position and decided to maintain status *quo ante* until the disposal of the review case.

4.1. Several reminders were issued to the KPT to furnish its written submission after discussing the matter in its Board of Trustees meeting. The Port continued to affirm that the matter would soon be discussed by its Board of Trustees. Reconstitution of the Board, earthquake in the Kutch area, etc., were shown as reasons for the delay.

4.2. The KPT vide its letter dated 2 April 2001 has informed that the proposal for revision of the rate structure of the Gandhidham township lands was included in the agenda for the Board meeting held on 2 March 2001; and, the Board resolved to request this Authority to continue with the stay granted earlier, in view of the heavy damages to the economy and civil structures in Adipur — Gandhidham — Kandla Complex caused by the unprecedented earthquake on 26 January 2001.

5. The response from the KPT has already been delayed considerably. In the meanwhile, a severe earthquake had hit the Kutch area. The request now made by the Board of KPT citing the extraordinary situation prevailing in this region, as an aftermath of the earthquake, is reasonable; and, is accordingly, accepted.

6. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority decides to extend the stay granted for implementation of the Order dated 29 October 1999 relating to revision of the rate structure of the Gandhidham Township lands of the KPT for a further period of six months from the date of publication of this Order in the Gazette of India. This Authority also directs the KPT to adhere to the extended time period for furnishing its written submission, failing which this Authority will be compelled to move *suo motu* in the matter.

S. SATHYAM, Chairman

[No. ADVT/III/IV/143/01-Exty.]

